

आयकर आयुक्त, उदयपुर

बनाम

मैसर्स हिंदुस्तान जिक लिमिटेड

18 मई, 2007

{एसएच कपाडिया एवं बी सुदर्शन रेड्डी, जेजे.}

अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन एक सरकारी कंपनी निर्धारिती द्वारा जिक सांद्रण के संचित स्टॉक का निर्यात& भारत औसत लागत/घरेलू मूल्य से कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तय करना& लेखांकन वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में वृद्धि जिसके दौरान ऐसा स्टॉक जमा हुआ की शुद्धता का अभिनिर्धारण - अतीत में निर्धारिती घरेलू कीमतों पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर संबंधित वस्तु का मूल्यांकन करता रहा है जहां वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों से कम थीं। इन परिस्थितियों में ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में सही कहा कि यदि पिछली लेखांकन नीति के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया गया होता, तो कंपनी का लाभ एक निश्चित राशि से अधिक होता। इसके अलावा, अभी कोई नुकसान की आशंका नहीं है लेकिन वर्तमान मामले में संभावित लाभ में कमी - इसलिए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में मूल्यांकन में किए गए परिवर्धन को हटाकर गलती की।

प्रतिवादी/निर्धारिती एक सरकारी कंपनी जिंक सांद्रण के उत्पादन और उसका उपयोग करने के व्यवसाय में लगी हुई थी। निर्धारण वर्ष 1996&97 के दौरान भारी मात्रा में जिंक सांद्रण जमा हो गया और निर्धारिती के लिए एफ संचित मात्रा का उपभोग करना संभव नहीं था। चूंकि संचित स्टॉक की घरेलू खपत संभव नहीं थी] इसलिए निर्धारिती ने संचित स्टॉक के निर्यात की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया। सरकार की अनुमति से निर्धारिती ने 31-3-1996 को लंदन मेटालिक एक्सचेंज (एलएमई मूल्य को अपनाकर बिक्री के उद्देश्य से जिंक कंसंट्रेट का मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया हालांकि एलएमई मूल्य भारत औसत लागत से 27-08 करोड़ रुपये कम था। लेखा परीक्षकों ने भी कुछ सिफारिशों कीं तदनुसार मूल्यांकन अधिकारी ने 31-3-1996 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के अतिरिक्त की। एओ के आदेश से व्यथित निर्धारिती&प्रतिवादी ने अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की जिसे प्राधिकारियों ने आंशिक रूप से अनुमति दे दी। निर्धारिती ने आईटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की] जिसे ट्रिब्यूनल ने राजस्व को निर्धारिती की आय में की गई बढ़ोतरी को हटाने का निर्देश देकर अनुमति दे दी। व्यथित होकर राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष

अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील।

राजस्व का तर्क है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारिती के पास गणना पद्धति को बदलने का कोई कारण नहीं था। 31-3-1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई थी इसलिए 31-3-1997 को समाप्त होने वाले अगले लेखांकन वर्ष में निर्यात बिक्री के तथ्य को ध्यान में रखने का कोई सवाल ही नहीं था ऐसा कोई आरोप नहीं था कि संचित स्टॉक और जिंक सांद्रण कबाड़ था जिसका भारत में कोई बाजार नहीं था। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि यदि पिछले वर्षों की लेखांकन नीति का पालन किया जाता तो उस स्थिति में लाभ में 27-08 करोड़ रुपये की वृद्धि होती। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनजर विभाग निर्धारिती की आय में वापस जोड़ने में सही था और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय यह कहने के लिए निर्धारिती के लिए खुला नहीं था कि एलएमई मूल्य के आधार पर अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का परिणाम घाटे में हुआ। यह कि यह डब्ल्यूएसी से कम था और मूल्य में कमी हुई थी और लेखांकन सिद्धांतों के तहत भी हालांकि मूल्य में कमी स्वीकार्य थी यह केवल उसी वर्ष में संभव था जिसमें यह हुआ था और चूंकि वर्तमान मामले में वित्तीय वर्ष

1995&96 में कोई निर्यात बिक्री नहीं थी इसलिए निर्धारिती था एलएमई मूल्य के आधार पर मूल्य में कमी का दावा करने का हकदार नहीं है।

निर्धारिती/प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि संचित स्टॉक का भारत में बिक्री के लिए कोई बाजार नहीं है यह कि निर्धारिती एक सरकारी कंपनी थी जिंक सांद्रण के संचित स्टॉक में धातु की मात्रा कम थी और इसमें सिलिका की अशुद्धता का स्तर अधिक था और इसलिए यह कैप्टिव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था इस परिस्थितियों में सरकार की अनुमति से निर्धारिती को उस मात्रा को अलग करना होगा जो कैप्टिव उपभोग के लिए सक्षम थी और स्टॉक का शेष जो कैप्टिव उपभोग के लिए सक्षम नहीं था और जिसे बेचा जाना था उस संचित स्टॉक के लिए भारत में कोई खरीदार नहीं थे यह कि लेखापरीक्षक इस तरह के पृथक्करण को पहचानने में विफल रहे। इन परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 1995 & 96 के दौरान एक नई वस्तु अस्तित्व में आई जिसे एक नया लेखांकन उपचार देना पड़ा यह कि विवेकपूर्ण लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारिती ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि से अधिक वर्तमान परिसंपत्तियों को आगे नहीं बढ़ाया और इसलिए बिक्री के लिए पहचानी गई मात्रा का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया था। एलएमई [लंदन मेटालिक एक्सचेंज] मूल्य के आधार पर निर्धारिती ने लेखांकन मानकों के माध्यम से भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा

मान्यता प्राप्त स्वीकृत लेखांकन अभ्यास पर कार्य किया है यह कि 31-3-1996 को एलएमई कीमत उक्त वस्तु के बाजार मूल्य का सबसे अच्छा अनुमान था यह कि राजस्व प्रत्याशित हानि के सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहा है जो समापन स्टॉक का मूल्यांकन करता है और यह कि वर्तमान मामले में लागत से कम पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारिती के लिए खुला था।

अपील स्वीकार की जा रही है

न्यायालय के द्वारा यह धारित किया गया कि

1-1 वर्तमान मामले में शामिल संकीर्ण विवाद यह है कि क्या निर्धारिती ने लंदन मेटालिक एक्सचेंज मूल्य पर अपने शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाकर लागत मूल्य के नीचे इन्वेंट्री जिक सांद्रण लिखने में सही किया था न कि घरेलू कीमत पर इसके वास्तविक वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाकर। [पैरा 10] [309&ए] बी]

1.2 वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि 31.3.96 को, जिक सांद्रण की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमत से कम थीं। इसके अलावा, अतीत में निर्धारिती घरेलू कीमतों पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जस्ता सांद्रता का मूल्यांकन करता रहा है। यही कारण है कि लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पिछली

लेखांकन नीति (घरेलू कीमतों पर) के अनुसार अनुमानित होता तो कंपनी का मुनाफा 27.08 करोड़ रुपये अधिक होता। लेखा परीक्षकों की यह रिपोर्ट गलत नहीं है जैसा कि निर्धारिती की ओर से आग्रह किया गया है। [पैरा 10] [309&बी सी]

1.3 यह प्रत्याशित हानि का मामला नहीं है, यह संभावित लाभ में कमी का मामला है। इसलिए, आईटीएटी ने मूल्यांकन में किए गए परिवर्धन को हटाने में गलती की थी। [पैरा 10 o 11] [309&डी व इ]

चैनरूप संपतराम बनाम आयकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल (1953) 24 आइटीआर 481 एससी एवं आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड (1991) 188 आइटीआर 44 एससी पर आधारित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 1179@2007

डी-बी- आयकर अपील नंबर 25/2003 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतिम फैसला व आदेश दिनांकित 14-11-2005 से।

पी.पी. मल्होत्रा, एएसजी, के.के. सैंथिवेलन, चेतन चावला और बी.वी. बालारामदास अपीलांट की ओर से।

के-संपत, लक्ष्मी अयंगर, आरके राघवन, एस कृष्णन और रानी छाबरा रेस्पॉडेंट की ओर से।

न्यायालय का निर्णय कपाडिया, जे. के द्वारा दिया गया।

1- एक संक्षिप्त प्रश्न जो इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए उठता है: क्या आईटीएटी को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कानून में उचित ठहराया गया था, कि "जिंक कंसंट्रेट" के समापन स्टॉक के मूल्यांकन के लिए निर्धारिती द्वारा अपनाई गई विधि अंतरराष्ट्रीय दर पर, क्रम में था, खासकर जब 31.3.96 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ था और खासकर जब अतीत में निर्धारिती भारत औसत लागत पर कैप्टिव खपत के लिए जिंक सांद्रण के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कर रहा था। इस सिविल अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं।

2. प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी-निर्धारिती एक सरकारी कंपनी थी। इस सिविल अपील में हम मूल्यांकन वर्ष 1996-97 से संबंधित हैं। निर्धारिती जिंक सांद्रण के उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ था जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा निजी तौर पर किया जाता था। मूल्यांकन वर्ष 1996-97 के दौरान, जिंक सांद्रण 84000 मीट्रिक टन (लगभग) तक जमा हो गया। उक्त मात्रा का उपभोग करना संभव नहीं था क्योंकि संचित स्टॉक में धातु की मात्रा कम थी और सिलिका की अशुद्धता का स्तर अधिक था। इसके अलावा, भारत में किसी अन्य संयंत्र में व्यवहार्य तरीके से जिंक सांद्रण का उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। चूंकि संचित स्टॉक की घरेलू

खपत संभव नहीं थी, इसलिए निर्धारिती ने संचित स्टॉक के निर्यात की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया। आगे 1991 में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप भारत में वैश्वीकरण आया। इसलिए, निर्धारिती-कंपनी ने सरकार के परामर्श से जिंक सांद्रण की संचित मात्रा का निर्यात करने का निर्णय लिया। सरकार की अनुमति से, निर्धारिती ने बिक्री के उद्देश्य से लंदन मेटालिक एक्सचेंज मूल्य (संक्षेप में, 'एलएमई मूल्य) को अपनाकर "जस्ता सांद्रण" का मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि 31.3.1996 को एलएमई मूल्य कम था। भारत औसत लागत (संक्षिप्त के लिए, 'डब्ल्यूएसी' 27.08 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, एओ ने यह विचार किया कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान जिंक सांद्रण की कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई थी; लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में था एक स्पष्ट अवलोकन कि इन्वेंट्री के मूल्य में 27.08 रुपये की कमी हुई जो कि कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं थे और यदि इन्वेंट्री का मूल्य घरेलू मूल्य पर लगाया गया होता तो कंपनी का लाभ 27.08 करोड़ रुपये से अधिक होता। एओ के अनुसार, उपरोक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनजर, 31.3.96 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में वृद्धि करने की मांग की गई थी। निर्धारिती-प्रतिवादी के अनुसार, एओ द्वारा लगाया गया यह आरोप कि उक्त वर्ष के दौरान कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई थी, प्रासंगिक नहीं था क्योंकि माल स्टॉक में पड़ा हुआ था और उन्हें अगले वर्षों में बेचा



जाना था। निर्धारिती के अनुसार, माल वास्तव में बाद के वर्षों में भारत से बाहर निर्यात किया गया था।

3. एओ के आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती-प्रतिवादी ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने इस मामले को आईटीएटी के समक्ष अपील में आगे बढ़ाया, जिसने निर्धारिती की आय में की गई बढ़ोतरी को हटा दिया।

4. आईटीएटी के निर्णय से व्यथित होकर, विभाग ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की, जिसकी राय थी कि विभाग द्वारा सुझाए गए कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए नहीं उठता। इसलिए यह सिविल अपील है।

5. विभाग की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पीपी मल्होत्रा ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारिती के पास लेखांकन की पद्धति को बदलने का कोई कारण नहीं है। यह आग्रह किया गया था कि 31.3.96 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई थी और इसलिए, 31.3.97 को समाप्त होने वाले अगले लेखा वर्ष में निर्यात बिक्री के तथ्य को ध्यान में रखने का कोई सवाल ही नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि संचित स्टॉक और जिक सांद्रण एक कबाड़ था जिसका भारत में कोई बाजार नहीं था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि

वर्तमान मामले में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि यदि पिछले वर्षों की लेखांकन नीति का पालन किया जाता तो उस स्थिति में लाभ में 27.08 करोड़. रु की वृद्धि होती। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनजर विभाग 31-3-96 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में जोड़ने में सही था।

6. दूसरी ओर, निर्धारिती/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. संपत ने प्रस्तुत किया कि संचित स्टॉक का भारत में बिक्री के लिए कोई बाजार नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि निर्धारिती एक सरकारी कंपनी थी; जिनका सांद्रण के संचित स्टॉक में धातु की मात्रा कम थी और इसमें सिलिका की अशुद्धता का स्तर अधिक था और इसलिए, यह कैप्टिव खपत के लिए उपयुक्त नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार की अनुमति से, निर्धारिती को उस मात्रा को अलग करना होगा जो कैप्टिव उपभोग के लिए सक्षम थी और स्टॉक का शेष जो कैप्टिव उपभोग के लिए सक्षम नहीं था और जिसे बेचा जाना था। हालाँकि, संचित स्टॉक के लिए भारत में कोई खरीदार नहीं था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि स्टॉक का जो हिस्सा बेचा जाना था वह एक नई वस्तु है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लेखा परीक्षक इस तरह के अलगाव को पहचानने में विफल रहे। इन परिस्थितियों में,

निर्धारिती के अनुसार, वितीय वर्ष 1995-96 के दौरान एक नई वस्तु अस्तित्व में आई जिसे एक नया लेखांकन उपचार दिया जाना था। इस संबंध में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 10.8.98 के पत्र पर भरोसा किया जिसमें निर्धारिती ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय दर में जिंक सांद्रण की कीमतों में गिरावट का रुख दिखाया गया है और इसलिए, सूची को लिखना आवश्यक हो गया है, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक। विवेकपूर्ण लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार, निर्धारिती ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि से अधिक वर्तमान परिसंपत्तियों को आगे नहीं बढ़ाया और इसलिए, बिक्री के लिए पहचानी गई मात्रा का मूल्यांकन एलएमई मूल्य के आधार पर निर्यात से शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इसलिए, निर्धारिती ने लेखांकन मानकों के माध्यम से भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त स्वीकृत लेखांकन अभ्यास पर काम किया है। यह आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड पत्र मूल्यांकन आदेश (एसएलपी पेपर बुक के पृष्ठ 47 पर) में नोट किया गया है। इस संबंध में विद्वान वकील ने नीचे उल्लिखित अधिकारियों पर भरोसा जताया। आगे यह आग्रह किया गया कि 31.3.96 को एलएमई मूल्य उक्त वस्तु के बाजार मूल्य का सबसे अच्छा अनुमान था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र पर भी भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि विभाग लेखांकन मानकों आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड से

विचलित होने का हकदार नहीं है। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विभाग अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय प्रत्याशित हानि के सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में कम लागत पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारिती के लिए खुला था। आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड।

7. जवाब में विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री पीपी मल्होत्रा ने आग्रह किया कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट मूल्यांकन आदेश का आधार है। यह बताया गया कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय निर्धारिती के लिए यह कहना संभव नहीं था कि एलएमई मूल्य के आधार पर अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के परिणामस्वरूप हानि हुई; यह WAC से कम था और मूल्य में कमी आई थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लेखांकन सिद्धांतों के तहत भी हालांकि मूल्य में कमी स्वीकार्य थी, यह केवल उसी वर्ष में संभव था जिसमें यह हुआ था और चूंकि वर्तमान मामले में वित्तीय वर्ष 1995-96 में कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई थी, इसलिए निर्धारिती एलएमई मूल्य के आधार पर मूल्य में कमी का दावा करने का हकदार नहीं था।

8. चेनरूप संपतराम बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल के मामले में, (1953) 24 आईटीआर 481 एससी, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि लेखांकन अवधि के अंत में बिना बिके स्टॉक का मूल्यांकन उस अवधि के व्यापारिक परिणामों को निर्धारित करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा था। इसे मुनाफ़े का स्रोत नहीं माना जा सकता। अंतिम स्टॉक, चाहे वह कहीं भी मौजूद आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड हो, को ट्रेडिंग खाते में लाने के बाद ही लाभ का सही ढंग से पता लगाया जा सकता है। आगे यह माना गया कि बिना बिके स्टॉक के मूल्य को क्रेडिट करने का असली उद्देश्य उनकी खरीद के समय खाते के दूसरी तरफ दर्ज किए गए सामान की लागत को संतुलित करना है ताकि उसी स्टॉक से संबंधित प्रविष्टियों को रद्द करने पर खाते के दोनों ओर से केवल वही लेनदेन छोड़े जाएंगे जिनमें वर्ष के दौरान वास्तविक बिक्री हुई है और इस प्रकार वह वर्ष के व्यापार पर वास्तव में प्राप्त लाभ या हानि दिखाएगा। ट्रेडिंग खाते में दिखाई देने वाले स्टॉक की प्रविष्टि का उद्देश्य केवल खरीदे गए सामान के लिए शुल्क को रद्द करना है, जो आवश्यक रूप से सामान की लागत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यदि यह लागत से अधिक या कम है, तो इसका प्रभाव वास्तव में बेची गई वस्तु पर लाभ बताना है। सिद्धांत से एक अपवाद है, अर्थात्, खाते बनाने की तिथि पर बाजार मूल्य को अपनाना, यदि वह मूल्य लागत से कम है। यह अगले वर्ष माल पर होने वाले नुकसान की आशंका में है। जबकि प्रत्याशित हानि को ध्यान में

रखा जाता है, समापन स्टॉक के सराहनीय मूल्य के रूप में प्रत्याशित लाभ को खाते में नहीं लाया जाता है क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यापारी वास्तविक वसूली से पहले बढ़ा हुआ मुनाफा दिखाने की परवाह नहीं करेगा। यह सिद्धांत कि समापन स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए, अब आम तौर पर वाणिज्यिक प्रथाओं और लेखांकन के स्थापित नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है।

9. इसी प्रकार का प्रभाव इस न्यायालय के निर्णय आयकर आयुक्त बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड (1991) 188 आईटीआर 44 एससी में है- उक्त निर्णय में यह माना गया है कि लाभ और हानि खाते में स्टॉक-इन-ट्रेड के मूल्य को शुरुआत में और लेखांकन वर्ष के अंत में बाजार लागत पर दर्ज करना वाणिज्यिक लेखांकन का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। कीमत, जो भी कम हो. जहां बाजार मूल्य मूल्यांकन की तारीख से पहले गिर गया है और जहां उस तारीख को वस्तु का बाजार मूल्य उसकी वास्तविक लागत से कम है, तो निर्धारित बाजार मूल्य पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने का हकदार है और इस प्रकार उस नुकसान का अनुमान लगाता है जो उसे हो सकता है। आगे यह माना गया कि लेखांकन का सही सिद्धांत लागत पर स्टॉक को खाते की किताबों में दर्ज करना है, जब तक कि मूल लागत से नीचे माल के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण मूल्य कम करने की आवश्यकता न हो। । इसलिए, आमतौर पर,

माल को लागत मूल्य से नीचे नहीं लिखा जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां कोई वास्तविक या प्रत्याशित हानि हो। दूसरी ओर, यदि कीमत में गिरावट केवल इतनी है कि इससे केवल संभावित लाभ में कमी आएगी, तो लागत पर प्रारंभिक मूल्यांकन को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

10. वर्तमान मामले में शामिल संकीर्ण विवाद यह है कि क्या निर्धारिती ने एलएमई मूल्य पर अपने शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाकर लागत मूल्य से नीचे इन्वेंट्री (जस्ता सांद्रता) लिखने में सही किया था, न कि घरेलू कीमत पर इसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाकर। वर्तमान मामले में कोई विवाद नहीं है कि 31.3.96 को ज़िंक सांद्रण की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों से कम थीं। इसके अलावा, अतीत में निर्धारिती घरेलू कीमतों पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जस्ता सांद्रता का मूल्यांकन करता रहा है। यही कारण है कि लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पिछली लेखांकन नीति (घरेलू कीमतें पर) के अनुसार अनुमानित है। कंपनी का मुनाफा 27.08 करोड़ रुपये अधिक होता। लेखापरीक्षकों की यह रिपोर्ट गलत नहीं है क्योंकि इसमें निर्धारिती की ओर से आग्रह किया गया था। उक्त रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं किया गया है। ब्रिटिश पेंट्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि

कीमत में गिरावट का प्रभाव केवल संभावित लाभ को कम करने जैसा है (यदि कोई लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को देखे तो यही प्रतीत होता है) लागत पर मूल्यांकन को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, वर्तमान मामला प्रत्याशित हानि का मामला नहीं है, यह संभावित लाभ में कमी का मामला है।

11. उपरोक्त कारणों से, हमारा मानना है कि आईटीएटी ने मूल्यांकन में किए गए परिवर्धन को हटाने में गलती की है। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के रद्द कर दिया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।



[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नवीन कुमार किलानियां (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।